

[2023] 6 एस. सी. आर 419

/

भारत का सुरक्षा और विनियम बोर्ड v.

वी शंकर

(2023 की सिविल अपील संख्या 527) फरवरी 08,2023

/

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला, जे जे।]

एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998-विनियम 19 (3)-की व्याख्या-एस. ई. बी. आई. के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यू. टी. एम.) द्वारा डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डी. सी. एच. एल.), इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव-प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था-प्रत्यर्थी पर Rs.10 लाख का जुर्माना लगाया गया था-प्रत्यर्थी को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया गया था कि वह कंपनी सचिव था जब कंपनी द्वारा विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए Rs.270 करोड़ का पुनर्खरीद प्रस्ताव दिया गया था-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अलग किया गया आदेश-अपील पर कहा गया:विनियमन 19 (3) कंपनी से एक अनुपालन अधिकारी और एक निवेशक सेवा केंद्र को नामित करने की अपेक्षा करता है-पुनर्खरीद विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामांकन का उद्देश्य दो गुना है; और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए-विनियमों की व्याख्या करने में न्यायाधिकरण की ओर से एक पेटेंट त्रुटि है-न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी की भूमिका, जो एक कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी थी, निवेशकों की शिकायतों के निवारण तक सीमित थी-निष्कर्ष पर पहुंचने में, न्यायाधिकरण विनियमन 19 (3) के बाद के भाग पर भरोसा करता है जो निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित है-हालांकि, न्यायाधिकरण इस महत्वपूर्ण बिंदु से चूक गया कि अनुपालन अधिकारी को भी पुनर्खरीद विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जैसा कि विनियमन 19 (3) में स्पष्ट रूप से आक्षेपित किया गया है।s.12A (a), (b) और (c),s.15HA-कंपनी अधिनियम 1956-ss.68, 77 ए-भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (धोखाधड़ी और अनुचित का निषेध)

/

/

/

/

/

/

419 ए.

420 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

प्रतिभूति बाजार) विनियम 2003-विनियम 3 (ए)-(डी), 4 (1), 4 (2) (एफ), (के) और (आर) से संबंधित व्यापार व्यवहार।

श्री भुवनेश्वर मिश्रा बनाम एस. ई. बी. आई.

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ता. **31** जुलाई **2014** में

2014 की अपील संख्या **7**); ब्रूक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड और

अन्य बनाम एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय। 21 मार्च 2018 2016 की अपील संख्या 266 में)-संदर्भित।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 527

2023.

/

2022 की अपील संख्या 283 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांक 01.11.2022 के निर्णय और आदेश से।

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, अभिषेक आनंद, सुश्री उन्नीमाया एस., मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

सोमशेखर सुंदरेसन, लक्ष्मीश एस. कामत, सुश्री समृति आहूजा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।
न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

/

1. स्वीकार करें।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 2 की धारा 15Z के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 1 द्वारा अपील प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण 3 के 1 नवंबर 2022 के निर्णय से उत्पन्न होती है।

/

3. न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, 22 मार्च 2022 के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसअंतर्गत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 68 और 77 ए और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1), 4 (2) (एफ), (के) और (आर) का उल्लंघन करने के लिए प्रत्यर्थी पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

/

1 "एस. ई. बी. आई "

2 "SEBI अधिनियम "3" न्यायाधिकरण "4" WTM "

/

421

भारत का सुरक्षा और विनियम बोर्ड v.

वी शंकर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

नियम 2003 5 को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12 ए (ए), (बी) और (सी) के साथ पढ़ा जाता है।

4. प्रतिवादी दो साल के लिए डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड 6 का कंपनी सचिव था, 2009-10 और 2010-11।

5. 3 अगस्त 2017 को, एस. ई. बी. आई. के डब्ल्यू. टी. एम. द्वारा डी. सी. एच. एल., इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिवादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए, जिसके बाद जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने पूछताछ में भाग लिया। डब्ल्यू. टी. एम. ने प्रत्यर्थी को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया कि वह वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी सचिव था जब कंपनी द्वारा नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 270 करोड़ रुपये का पुनर्खरीद प्रस्ताव दिया गया था।

/

/

6. डब्ल्यू. टी. एम. ने पाया कि प्रतिवादी ने कंपनी सचिव के रूप में अपनी क्षमता में पुनर्खरीद के लिए सार्वजनिक घोषणा पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रत्यर्थी के खिलाफ निष्कर्ष यह था कि कंपनी के एक 'सांविधिक अधिकारी' के रूप में, उसे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली सार्वजनिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित परिश्रम करना चाहिए था और पुनर्खरीद प्रस्ताव दस्तावेजों की सत्यता और कानूनी अनुपालन की जांच करनी चाहिए थी। डब्ल्यू. टी. एम. ने प्रत्यर्थी को पर्याप्त निशुल्क भंडार के बिना अपने इक्विटी शेयरों के पुनर्खरीद के संबंध में कंपनी के आचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसने निवेशकों/शेयरधारकों को गुमराह किया था। प्रतिवादी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 68 और 77 ए के प्रावधानों और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. अधिनियम के संज्ञानात्मक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

7. अपील में, डब्ल्यूटीएम के आदेश को न्यायाधिकरण द्वारा 1 नवंबर 2022 को रद्द कर दिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा जिन निष्कर्षों पर पहुंचा गया है, उन्हें आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 14 और 15 में समाहित किया गया है। न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के दौरान कहा है कि एक बार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव और तुलनपत्र को मंजूरी दिए जाने के बाद, कंपनी सचिव का कर्तव्य "केवल तुलनपत्र और प्रस्ताव दस्तावेज में दर्शाई गई सामग्री को प्रमाणित करना" था। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण के अनुसार, प्रत्यर्थी को पुनर्खरीद प्रस्ताव दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अनुपालन करने का दायित्व अनिवार्य रूप से रखा गया था

/

/

/

/

5 "पीएफयूटीपी विनियम "6" डीसीएचएल "

/

422

/

[2023] 6 एस सी आर।

निदेशक मंडल और कंपनी सचिव के रूप में प्रतिवादी पर नहीं, न्यायाधिकरण ने एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 1998 के विनियम 19 (3) के प्रावधानों पर भरोसा किया है जो निम्नलिखित शर्तों में है: "19(3) कंपनी खरीद-वापसी नियमों के अनुपालन और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अनुपालन अधिकारी और निवेशक सेवा केंद्र को

नामित करेगी। "8. जिस तरीके से न्यायाधिकरण ने उपरोक्त विनियमन का अर्थ लगाया है, वह आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 18 में इंगित किया गया है जो इस प्रकार है:

/

"18. उपरोक्त प्रावधान इंगित करता है कि कंपनी निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगी। कंपनी सचिव होने के नाते अपीलार्थी एक अनुपालन अधिकारी भी था और इस प्रकार अनुपालन अधिकारी की भूमिका केवल निवेशकों की शिकायतों के निवारण तक सीमित थी। "9. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार आग्रह करते हैं कि:

/

/

(i) प्रत्यक्षतः, विनियमन 19 (3) पर रखी गई व्याख्या गलत है;

((ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 ए, जो कंपनी की अपनी प्रतिभूतियां खरीदने की शक्ति से संबंधित है, विभिन्न आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।

/

(iii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 215 के संदर्भ में, बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते को बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले और लेखा परीक्षकों को उनकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

/

((iv) प्रमाणीकरण का कर्तव्य केवल प्रासंगिक वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तक सीमित नहीं हो सकता है।

(v) प्रतिवादी की ओर से एक पेटेंट विफलता थी क्योंकि एक कंपनी सचिव के रूप में, वैधानिक अनुपालनों को विधिवत प्रमाणित करना उसका कर्तव्य था;

/

(vi) न्यायाधिकरण ने उन्हें इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया कि अनुपालन सुनिश्चित करना निदेशक मंडल का काम है; और

/

(vii) आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 18 में इस आशय का अवलोकन कि कंपनी सचिव की भूमिका केवल निवेशकों की शिकायतों के निवारण तक ही सीमित है, स्पष्ट रूप से विनियमन 19 (3) के विपरीत है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश वकील श्री सोमशेखर सुंदरेसन ने कहा कि:

/

(i) जो प्राथमिक निष्कर्ष निकाला गया है, वह वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने में निदेशक मंडल की विफलता के संबंध में है;

((ii) प्रत्यर्थी कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर रहा था और निदेशक मंडल की ओर से चूक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

/

(iii) इसके अलावा, निष्कर्ष यह है कि कंपनियों के खाते गलत पाए गए और चूक निदेशक मंडल के पास है न कि कंपनी सचिव के पास। 11. एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम 1998 के विनियम 19 (3) में कंपनी को एक अनुपालन अधिकारी और एक निवेशक सेवा केंद्र को नामित करने की आवश्यकता है। नामांकन का उद्देश्य दो गुना है, अर्थात् (i) पुनर्खरीद विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना; और (ii) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना। विनियमों की व्याख्या करने में न्यायाधिकरण की ओर से एक पेटेंट त्रुटि है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी की भूमिका, जो एक कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी थी, निवेशकों की शिकायतों के निवारण तक सीमित थी। निष्कर्ष पर पहुंचने में, न्यायाधिकरण ने विनियमन 19 (3) के बाद के भाग पर भरोसा किया है जो निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित है। न्यायाधिकरण द्वारा जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया है, वह यह है कि अनुपालन अधिकारी को पुनर्खरीद नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। विनियमों के विनियम 19 (3) में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है। चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा 19 (3) की व्याख्या पर जो व्याख्या की गई है, वह विनियमन 19 (3) की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है, इसलिए हम आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं और विनियमन 19 (3) के प्रावधानों पर ऊपर रखी गई व्याख्या के आलोक में तथ्यों पर नए सिरे से विचार करने के लिए कार्यवाही को न्यायाधिकरण को वापस भेज देते हैं।

/

/

/

/

12. वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने इस पर भरोसा जताया है

श्री भुवनेश्वर मिश्रा बनाम एस. ई. बी. आई. में न्यायाधिकरण के पूर्व निर्णय

(31 जुलाई 2014 को 2014 की अपील संख्या 7 में निर्णय लिया गया) और ब्रूक्स

/

424 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

लैबोरेटरीज लिमिटेड और अन्य बनाम एस. ई. बी. आई. (21 मार्च 2018 को निर्णय लिया गया)

2016 की अपील सं. 266)। प्रत्यर्थी की ओर से पेश वकील श्री सोमशेखर सुंदरेसन ने आग्रह किया है कि ये निर्णय अलग-अलग हैं। चूंकि हम नए सिरे से विचार के लिए कार्यवाही को वापस भेज रहे हैं, इसलिए हम वर्तमान अपील में जिन पूर्व निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उन पर पक्षकारों के अधिकारों और दलीलों को रिमांड पर न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला रखते हैं।

/

13. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुज्ञात जाती है और 1 नवंबर 2022 के न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को खारिज कर दिया जाता है। 2022 की अपील संख्या 283 को नए सिरे से निर्णय के लिए न्यायाधिकरण की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा।

/

14. न्यायाधिकरण उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का प्रयास करेगा जिस दिन इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके रिकॉर्ड में रखी गई है।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

